



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)  
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 27, 1994/माघ 7, 1915

No. 42]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 27, 1994/MAGHA 7, 1915

पर्यावरण और वन मंत्रालय

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1994

का.प्रा. 60 (अ) :- पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन एक प्रधिसूचना सं. का.प्रा. 80 (अ), तारीख 28 जनवरी, 1993 प्रकाशित की गई थी जिसमें जब तक कि उक्त प्रधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी प्रस्तावित न दे दी गई हो, तब तक भारत के किसी भी भाग में प्रारंभ किए जाने वाले क्रियाकलाप या नई परियोजनाओं के विस्तारण या प्राधुनिकीकरण के संबंध में निर्बंधन और प्रतिबंध अधिरोपित करने के केंद्रीय सरकार के आशय के विरुद्ध जनता से उक्त प्रधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के भीतर आक्षेप मांगे गए थे ;

और प्राप्त सभी आक्षेपों पर सम्यक् रूप से विचार किया गया है ;

अतः केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (अ) के खंड (अ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निवेश देती है कि इस प्रधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही किसी क्रियाकलाप का, यदि प्रदूषण भार विद्यमान प्रदूषण भार से अधिक है या इस प्रधिसूचना की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध नई परियोजना

भारत के किसी भाग में तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि इस प्रधिसूचना में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी प्रस्तावित न दे दी गई हो ।

2. परियोजना की पर्यावरण संबंधी प्रस्तावित प्राप्त करने के लिए प्रेषण और प्रक्रिया :

I. (क) कोई व्यक्ति जो भारत के किसी भाग में किसी परियोजना को प्रथम अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किसी विद्यमान उद्योग या परियोजना का विस्तारण या प्राधुनिकीकरण प्रारंभ करना चाहता है, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली को एक आवेदन भेजेगा ।

यह आवेदन इस प्रधिसूचना की (अनुसूची 2) में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में किया जाएगा और उसके साथ परियोजना की व्यरेवार रिपोर्ट होगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण संबंधी प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट और केंद्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार तैयार की गई पर्यावरण प्रबंध योजना होगी ।

(ख) आंकड़ों और कार्य योजना को प्रेषित अथवा अनुपयुक्त प्रस्तुत किए जाने के कारण प्रसूचित किए गए मामलों का पुर्विलोकन किया जा सकेगा जब भी उन्हें पूर्ण आंकड़ों और कार्य योजना के साथ प्रस्तुत किया जाता है । दूसरी बार अपूर्ण आंकड़ों

का प्रस्तुत किया जाना स्वयं ही प्रभाव निर्धारण अभिकरण के लिए मामले की संक्षेपतः अस्वीकृत करने के लिए पर्याप्त कारण होगा।

## II. निम्नलिखित स्थल-विनिर्दिष्ट परियोजनाओं की वशा में—

- (क) खनन ;
- (ख) पिट हेड ताप विद्युत केंद्र ;
- (ग) जल विद्युत मुख्य सिंचाई परियोजना और उसका संयोजन जिसमें बाढ़ नियंत्रण सम्मिलित है।
- (घ) पत्तन तथा बंदरगाह (लघु पत्तन को छोड़कर)

परियोजना प्राधिकारी कोई अन्वेषण या सर्वेक्षण प्रारंभ करते समय केंद्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को परियोजना स्थल के स्थान के बारे में सूचित करेंगे। केंद्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय तीस दिन की अधिकतम अवधि के भीतर प्रस्तावित स्थल की उपयुक्तता या अन्यथा के बारे में विनिश्चय सूचित करेगा। उक्त स्थल अनापत्ति ;

—किसी स्वीकृत क्षमता या खनन पट्टे के लिए ;

—500 हेक्टर या अधिक क्षेत्र में, यदि अपेक्षित हो, क्षमताओं के पूर्वावलोकन और खोज के लिए,

भंजूर की जाएगी और सन्निर्माण, संक्रिया या खनन प्रारंभ करने के लिए यह पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

III. (क) प्रायोजन के साथ प्रस्तुत की गई संक्षिप्त साध्यता रिपोर्ट का, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार के प्रभाव निर्धारण अभिकरण द्वारा, इस अधिसूचना की अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट संरचना वाली विशेषज्ञ समिति के परामर्श से मूल्यांकन और निर्धारण किया जाएगा। प्रभाव निर्धारण अभिकरण, संघ का पर्यावरण और वन मंत्रालय होगा। ऊपर वर्णित विशेषज्ञ समिति का गठन संबंधित प्रभाव निर्धारण अभिकरण या इस बाबत प्रभाव निर्धारण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अन्य निकाय द्वारा किया जाएगा।

(ख) उक्त विशेषज्ञ समिति को परियोजना से संबंधित संक्रियाओं के प्रारंभ से पूर्व, उनके दौरान या उसके पश्चात् किसी समय, यथास्थिति, स्थल या कारखाना परिसरों में प्रवेश करने और उनका निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(ग) प्रभाव निर्धारण अभिकरण परियोजना प्राधिकारियों द्वारा दिए गए दस्तावेजों, आंकड़ों, जो स्थलों अथवा कारखानों में की गई यात्राओं के दौरान संगृहीत आंकड़ों द्वारा अनुपूरित होंगे के तकनीकी निर्धारण और प्रभावित जनसंख्या और पर्यावरण संबंधी समूहों की अन्तःक्रिया पर आधारित सिफारिशें तैयार करेगा। विस्तृत पर्यावरणीय प्रबन्ध योजनाओं सहित संक्षिप्त साध्यता रिपोर्ट, सिफारिश और वे शर्तें, जिनके अध्याधीन रहने हुए पर्यावरण संबंधी अनापत्ति दी गई है, संबंधित पक्षकारों या पर्यावरण संबंधी समूहों को अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी। जनता के विचार यदि प्रभाव निर्धारण अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के प्राप्ति के 30 दिन भीतर ऐसी सिफारिश की जाए तो इस प्रयोजन के लिए व्यवस्थित लोक सुनवाईयों में, ऐसी सुनवाई की कम से कम दो समाचारपत्रों में एक मास की सूचना देने के पश्चात् मांगे जा सकेंगे।

जनता को परियोजना रिपोर्टों और पर्यावरणीय प्रबन्ध योजनाओं तक पहुँच की प्रभाव निर्धारण अभिकरण मुख्यालय में व्यवस्था की जाएगी।

निर्धारण परियोजना प्राधिकारियों से अपेक्षित दस्तावेजों और आंकड़ों की प्राप्ति से तीन मास की अवधि के भीतर और जहाँ अपेक्षित हो वहाँ लोक सुनवाई की समाप्ति पर पूरा किया जाएगा और विनिश्चय उसके पश्चात् अधिकतम तीस दिन के भीतर सूचित कर दिया जाएगा। परियोजना के स्थापित किए जाने से संबंधित कोई प्रारम्भिक या अन्य कार्य पर्यावरणीय स्थल अनापत्ति प्राप्त किए जाने तक प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा।

IV. संबंधित प्रभाव निर्धारण अभिकरण की सिफारिशों के कार्यान्वयन और उन शर्तों को, जिनके अधीन पर्यावरण संबंधी अनापत्ति दी गई है, प्रभावी रूप से मानिटर करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से सम्बन्धित परियोजना प्राधिकारी संबंधी अभिकरण को छमाही रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगे। प्रभाव निर्धारण अभिकरण अनुपालन रिपोर्टें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगा।

यदि प्रभाव निर्धारण अभिकरण से समय सीमा के भीतर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है तो परियोजना उस रूप में अनमोदित कर ली समझी जाएगी जिस रूप में वह परियोजना प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावित की गई थी।

3. इस अधिसूचना की, कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी :

(क) अधिसूचना का.प्रा.सं. 102 (अ), तारीख 1 फरवरी, 1989 का.प्रा.सं. 114 (अ), तारीख 20 फरवरी, 1991 और का.प्रा. सं. 319 (अ), तारीख 7 मई, 1992 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अवस्थित या अवस्थान के लिए प्रस्तावित अनुसूची-1 की प्रविष्टि सं. 318 और 20 के अधीन आने वाली कोई भव।

(ख) अनुसूची 1 की प्रविष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 25, 27 के अधीन आने वाली कोई भव यदि विनिर्माण 50 करोड़ रुपये से कम हो।

(ग) लघु औद्योगिक सेक्टर के लिए प्रारंभित कोई भव जिसमें विनिर्माण एक करोड़ रुपये से कम का हो।

4. वास्तविक आंकड़ों को छिपाने या मिथ्या, भ्रामक आंकड़ों/रिपोर्टें, विनिश्चय या सिफारिशें प्रस्तुत किए जाने से परियोजना अस्वीकार हो जाएगी, अनमोदित भी, यदि मिथ्या आंकड़ों के आधार पर पहले दिया गया हो तो प्रतिसंहत हो जाएगा। भ्रामक और गलत जानकारी के अन्तर्गत निम्नलिखित आएंगे—

— मिथ्या जानकारी

—मिथ्या आंकड़े

—बनाई गई रिपोर्टें

—वास्तविक आंकड़ों का छिपाना

—मिथ्या सिफारिशें या विनिश्चय।

[सं. जेड 12013/4/89-1 ए-1]

भार. राजामणि, सचिव (पर्यावरण और वन)

अनुसूची-1

(पैरा 1 और 2 देखिए)

केंद्रीय सरकार से पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा करने वाली परियोजनाओं की सूची

1. न्यूक्लीयर पावर और संबंधित परियोजनाएं, जैसे भारी जल संयंत्र नाभिकीय ईंधन परिसर, विरल मुद्रा (रेअर अर्थ्स)।

2. नदी छोटी परियोजनाएं जिसमें जल विद्युत, मुख्य सिंचाई और उनके समुच्चय बाढ़ नियंत्रण सम्मिलित हैं।

3. पत्तन बंदरगाह और विमान पत्तन (नधु पत्तन और बंदरगाह के सिवाय)

4. पेट्रोलियम परिष्करण जिसमें अपरिष्कृत उत्पाद पाइपलाइन हैं।

5. एकल सुपरफास्फेट के अलावा अन्य रासायनिक उर्वरक (नाइट्रोजिनस और फास्फेटिक)।

6. नाणकजीव मार (तकनीकी)

7. पेट्रो-रासायनिक कॉम्प्लेक्स (ओपे फिनिक और एरोमेटिक दोनों), और रासायनिक मध्यवर्ती जैसे डी एम टी डीटरोलेक्टम सैब इत्यादि तथा एन एन पी डी ई, एच पी डी ई, पी पी, पी बी सी जैसे आधारीक प्लास्टिक का उत्पादन।

8. प्रपंज औषधि और वैयजिक

9. तेल और गैस की खोज तथा उनका उत्पादन, परिवहन और भंडारण।

10. गिगेटिक रबर।

11. एम्बेस्टोस और एस्बेस्टोस उत्पाद।

12. हाइड्रोसाइक्लिक ऐसिड और उसकी व्युत्पत्ति।

13. (क) प्राथमिक मौसम विज्ञानी उद्योग (जैसे लीह और इत्यादि एन्यूमीनियम, तांबा, जस्ता, सोना और फेब्रुएनार्यस का उत्पादन)

(ख) विद्युत मार्फ भट्टी।

14. क्लोर एल्काली उद्योग।

15. पेंटस के विनिर्माण में काम आने वाली जल्दरी कच्ची सामग्री और रेमिन के विनिर्माण सहित सम्बन्धित पेंट कॉम्प्लेक्स।

16. विगकोस स्टेपल फाइबर और फिलामेंट यार्न। -

17. सीरा और मीना एन्टीमनी एलाय के आक्साइडों के विनिर्माण के साथ सम्बन्धित स्टोरेज बैटरियां।

18. समुद्र की उच्च जल रेखा के 200 मीटर से 500 मीटर के बीच समस्त पर्यटन और परियोजनाएं तथा 5 करोड़ से अधिक निवेश के साथ 1000 मीटर से अधिक उत्पादन के अवस्थान पर।

19. तापीय विद्युत संयंत्र।

20. खनन परियोजनाएं (5 हेक्टर से अधिक के लिए पट्टे सहित)

21. राजमार्ग परियोजनाएं

22. हिमालय शृंखला में कोलतारी सड़कें और वनीय क्षेत्र

23. आसवनियां

24. अपरिष्कृत खाल और चर्म

25. लुगरी, कागज और अखबारी कागज

26. रंजक

27. सीमेंट

28. दलार्धर (व्यष्टिक)

29. विद्युतसेपन

अनुसूची-2

[पैरा 3 का उप-पैरा 1 (क) देखिए]

भावदेन-प्रकृप

1. (क) प्रस्तावित परियोजना का नाम व पता ;

(ख) परियोजना की अवस्थिति :

स्थान का नाम :

जिला : तहसील :

अक्षांश/रेखांश :

निकटतम विमान पत्तन/रेल स्टेशन :

(ग) जांच किए गए बैकल्पिक स्थल तथा प्रस्तावित स्थल का चयन करने के लिए कारण ;

(घ) क्या यह स्थल स्थानीय भूमि प्रयोग योजना के अनुसार अनुबद्ध भूमि प्रयोग के अनुरूप है।

2. परियोजना के उद्देश्य ;

3. (क) अपेक्षित भूमि :

कृषि भूमि :

अन भूमि तथा वनस्पति का घनत्व

अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

(ख) (1) आवाह क्षेत्र/प्रस्तावित स्थल के 10 कि.मी. की परिधि में भूमि प्रयोग ;

(2) क्षेत्र की स्थलाकृति, जिसमें ढाल पहलू और ऊंचाई उपबोधित की गई हो ;

(3) प्रस्तावित भूमि का क्षरण वर्गीकरण।

(ग) 10 कि.मी. की परिधि में विद्यमान प्रदूषण स्रोत तथा वायु, जल और भूमि की गुणवत्ता पर उनका प्रभाव ;

(घ) निकटतम राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य/जीवमंडल आरक्षित/स्मारकों ऐतिहासिक स्थलों/आरक्षित वनों की दूरी ;

(ङ) खदानों/उधार क्षेत्रों के लिए पुनरुद्धार योजना ;

(च) हरित पट्टी योजना ;

(छ) प्रतिकारात्मक वनरोपण योजना।

4. जलवायु और वायु गुणवत्ता :

(क) स्थल पर पवनारेख ;

(ख) अधिकतम/न्यूनतम/औसत वार्षिक तापमान ;

(ग) प्रतिशतमान की आर्द्रता ;

(घ) चक्रवातों/तूफानों/बावल फटने की आकृति ;

(ङ) परिवेशी वायु गुणवत्ता मापकें ;

(च) परियोजना से एस पी एस, गैस (सी ओ सी ओ, एस ओ, एन ओ एक्स, सी एच, एन, आदि) के प्रसर्जन की प्रकृति और सान्द्रण।

5. जल सन्तुलन :

(क) स्थल पर जल सन्तुलन ;

(ख) क्षीण मौसम में जल की उपलब्धता ; जल की आवश्यकता ;

(ग) प्रतियोगी उपयोगताओं सहित दोहन किए जाने वाले स्रोत (नदी, झील, भूमि, सार्वजनिक आपूर्ति)

- (घ) जल गुणवत्ता ;  
(ङ) पिछले 15 वर्षों में भूमि जल की गुणवत्ता और मात्रा में देखे गए परिवर्तन तथा वर्तमान चार्जिंग और निकासी के ब्यौरे ;

(च) (1) शोधन ब्यौरे सहित छोड़े जाने वाले अपशिष्ट जल की मात्रा ;

(2) ठोस अपशिष्टों के ब्ययन से पूर्व और पश्चात प्रदूषण बॉडी में जल की मात्रा और गुणवत्ता ;

(3) भूमि पर छोड़े जाने वाले अपशिष्ट जल की मात्रा और भूमि की किस्म ;

(छ) (1) आवश्यक आवाह शोधन योजना सहित जलाशय जल गुणवत्ता के ब्यौरे ;

(2) कमांड क्षेत्र विकास योजना

6. ठोस अपशिष्ट :

(क) उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की प्रकृति और मात्रा ;

(ख) ठोस अपशिष्ट निपटान का तरीका ।

7. शोर और कंपन :

(क) शोर और कंपन के स्तर ।

(ख) परिवर्ती शोर स्तर ।

(ग) शोर और कंपन नियंत्रण के प्रस्तावित उपाय ।

(घ) प्रचलन समस्या, यदि कोई हो, और उसके नियंत्रण के उपाय ।

8. बिजली की आवश्यकता, जिसमें आपूर्ति के स्रोत का उल्लेख हो, यदि कैप्टिव बिजली इकाई लगाने का प्रस्ताव हो तो पूरा पर्यावरणीय ब्यौरा प्रलग से भेजें ।

9. लगाया जाने वाला चरम श्रमिक बल, जिसमें निम्न ब्यौरा दिया जाए :

— अपशिष्ट जल/वायु/मृदा जनित रोगों के कारण क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याएं ।

— विद्यमान और प्रस्तावित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली ।

10. (क) विस्थापित होने वाले गांवों और लोगों की संख्या

(ख) पुनर्वास वृहत् योजना ।

11. जोखिम निर्धारण रिपोर्ट तथा विपदा प्रबंध योजना ।

12. (क) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट (पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा) ;

(ख) पर्यावरणीय प्रबंध योजना (समय-समय पर जारी मार्ग-दर्शक सिद्धांतों के अनुसार तैयार) ;

(ग) विस्तृत व्यावहारिकता रिपोर्ट ;

(घ) विविधित भरी हुई प्रश्नावली ।

13. पर्यावरणीय प्रबंध कक्ष का ब्यौरा ।

इसमें यह बताना है कि ऊपर दिए गए प्रांकड़े और सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और मुझे इस बात की जानकारी है कि यदि प्रस्तुत किए गए प्रांकड़ों/सूचना का कोई भाग किसी भी समय मिथ्या या भ्रामक पाया जाता है तो परियोजना को नामंजूर

कर दिया जायेगा और परियोजना को बी गई घनापति, यदि कोई हो, को हमारी जोखिम और लागत पर वापस लिया जा सकेगा ।

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

(नाम और पूरे पते सहित)

आवेदक जिस संगठन की ओर से हस्ताक्षर कर रहा है उस संगठन की मोहर

टिप्पण : ऐसे मकों की बाबत जिसके लिए परियोजना प्रस्तावक की घोषणा के अनुसार प्रांकड़े अपेक्षित नहीं हैं या उपलब्ध नहीं हैं तो परियोजना पर उसी आधार पर विचार किया जाएगा ।

अनुसूची-3

[पैरा-3 का उप-पैरा (iii) (क) देखिए]

पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण के लिए विशेषज्ञ समितियों की संरचना

1. केन्द्र और राज्य स्तर पर विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन और निर्धारण निम्न प्रकार से गठित विशेष समितियों द्वारा किया जाएगा, जिनमें प्रत्येक क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे :—

1. पारिस्थितिक तंत्र प्रबंध

2. वायु/जल प्रदूषण नियंत्रण

3. जल संसाधन प्रबंध

4. वनस्पतिजात/प्राणिजात संरक्षण और प्रबंध

5. भूमि प्रयोग योजना

6. सामाजिक विज्ञान/पुनर्वास

7. परियोजना मूल्यांकन

8. पारिस्थितिकी

9. पर्यावरणीय स्वास्थ्य

10. विषय क्षेत्र विशेषज्ञ

11. गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि/पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित व्यक्ति ।

2. अध्यक्ष, उरकूट और अनुभवों पर स्थिति-विज्ञानी या पर्यावरणीय विद या तकनीकी व्यावसायिक या सुसंगत विकास क्षेत्र में बहुत प्रबंधकोय अनुभव का होगा ।

3. प्रभाव निर्धारण अभिकरण/केन्द्र/राज्य का प्रतिनिधि सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

4. अध्यक्ष और सदस्य प्रतिनिधियों के रूप में विनिर्दिष्ट रूप में नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को छोड़कर दैनिकीय दृष्टि से कार्य करेंगे ।

5. किसी समिति में 15 से अधिक सदस्य नहीं होंगे ।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 1994

S.O. 60(E).—Whereas a notification under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 inviting objections from the public within sixty days from the date of publication of the said notification, against the intention of the Central Government to impose restrictions and prohibitions on the expansion and modernization of any activity or new projects being undertaken in any part of India unless environmental clearance has been accorded by the Central Government or the State Government in accordance with the procedure specified in that notification was published as S.O. No. 80(E) dated 28th January, 1993;

And whereas all objections received have been duly considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby directs that on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette, expansion or modernization of any activity if pollution load is to exceed the existing one, or new project listed in Schedule I to this notification, shall not be undertaken in any part of India unless it has been accorded environmental clearance by the Central Government in accordance with the procedure hereinafter specified in this notification;

## 2 Requirements and procedure for seeking environment clearance of projects:

I(a) Any person who desires to undertake any project in any part of India or the expansion or modernisation of any existing industry or project listed in the Schedule shall submit an application to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, New Delhi.

The application shall be made in the proforma specified in Schedule II to this notification and shall be accompanied by a detailed project report which shall, inter alia, include an Environmental Impact Assessment Report and an Environment Management Plan prepared in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests from time to time.

(b) Case rejected due to submission of insufficient or inadequate data and Action Plans may be reviewed as and when submitted with complete data and Action Plans. Submission of incomplete data for the second time would itself be a sufficient reason for the Impact Assessment Agency to reject the case summarily.

## II In case of the following site specified projects:

- (a) mining;
- (b) pit-head thermal power stations;
- (c) hydro-power, major irrigation projects and/or their combination including flood control;
- (d) ports and harbours (excluding minor ports).

The project authorities will intimate the location of the project site to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests while initiating any investigation and surveys. The Central Government in the Ministry of Environment & Forests will convey a decision regarding suitability or otherwise of the proposed site within a maximum period of thirty days. The said site clearance will be granted for:

- a sanctioned capacity or for any mining lease;
- 500 ha or above area, if so required, for prospecting and exploration of minerals.

and it will be valid for a period of five years for commencing the construction, operation or mining.

III (a) The summary feasibility report submitted with the application shall be evaluated and assessed by the Impact Assessment Agency at the Central Government in consultation with a Committee of experts, having a composition as specified in Schedule-III of this Notification. The Impact Assessment Agency (IAA) would be the Union Ministry of Environment and Forests. The Committee of Experts mentioned above shall be constituted by the Impact Assessment Agency concerned or such other body under Central Government authorised by Impact Assessment Agency in this regard.

(b) The said Committee of experts shall have full right of entry and inspection of the site or, as the case may be, factory premises at any time prior to during or after the commencement of the operations relating to the project.

(c) The Impact Assessment Agency will prepare a set of recommendations based on technical assessment of documents and data, furnished by the project authorities supplemented by data collected during visits to sites or factories and interaction with affected population and environmental groups. Summary feasibility reports, along with the detailed Environmental Management Plans, the recommendation and the conditions subject to which environmental clearance is given shall be made available to the concerned parties or environmental groups on request. Comments of the public may be solicited, if so recommended by IAA within 30 days of receipt of proposal, in public hearings arranged for the purpose after giving one month notice of such hearings in at least two newspapers.

Public shall be provided access to the summary of the project reports and Environmental Management Plans at the Headquarters of the Impact Assessment Agency.

The assessment shall be completed within a period of three months on receipt of the requisite documents and data from the project authorities and completion of public hearing were required and decision conveyed within a maximum of 30 days thereafter. No work, preliminary or otherwise, relating to the setting up of the project may be undertaken till the environmental site clearance is obtained.

IV. In order to enable the Impact Assessment Agency concerned to monitor effectively the implementation of the recommendations and conditions subject to which the environmental clearance has been given, the project authorities concerned shall submit a half-yearly report to the concerned agency. Impact Assessment Agency will make compliance reports publicly available.

V. If no comments from the Impact Assessment Agency received within the time limit, the project would be deemed to have been approved as proposed by project authorities.

## 3. Nothing contained in this Notification shall apply to:

- (a) any time falling under entry Nos. 3, 18 and 20 of the Schedule-I to be located or proposed to be located in the areas covered by the Notification's SO No. 102(E) dated 1st February, 1989; S.O. 114(E) dated 20th February, 1991 and S.O. No. 319(E) dated 7th May, 1992
- (b) any item falling under entry Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 25 and 27 of Schedule-I if the investment is less than Rs. 50 crores.
- (c) any item reserved for Small Scale Industrial sector with investments less than Rs. 1 crore.

4 Concealing factual data or submission of false, misleading data/reports, decisions or recommendations would lead to the project being rejected-approval, if granted earlier on the basis of false data, would also be revoked. Misleading and wrong information will cover the following:

- False information.
- False data.
- Engineering reports.
- Concealing of factual data
- False recommendations or decisions.

[No. Z-12013/4/89-IA-I]  
R. RAJAMANI, Secy. (E&F)

## SCHEDULE—I

(See paras 1 and 2)

## LIST OF PROJECTS REQUIRING ENVIRONMENTAL CLEARANCE FROM THE CENTRAL GOVERNMENT

1. Nuclear Power and related projects such as Heavy Water Plants, nuclear fuel complex, rare earths.
2. River Valley projects including hydel power, major irrigation and their combination including food control.
3. Ports, Harbours, Airports (except minor ports and harbours).
4. Petroleum Refineries including crude and product pipelines.
5. Chemical Fertilizers (Nitrogenous and Phosphatic) other than single superphosphate).
6. Pesticides (Technical).
7. Petrochemical complexes (Both Olefinic and Aromatic) and Petro-chemical intermediates such as DMT, Caprolactam LAB etc. and production of basic plastics such as LLPDE, HPDE, PP PVC.
8. Bulk drugs and pharmaceuticals
9. Exploration for oil and gas and their production, transportation and storage.
10. Synthetic Rubber.
11. Asbestos and Asbestos products.
12. Hydrocyanic acid and its derivatives.
- 13 (a) Primary metallurgical industries (such as production of Iron and Steel, Aluminium, Copper Zinc, Lead and Ferror Alloys).
- (b) Electric arc furnaces (Mini Steel Plants).
14. Chlor alkali industry.
15. Integrated paint complex including manufacture of resins and basic raw materials required in the manufacture of paints.
16. Viscose Staple fibre and filament yarn.
17. Storage batteries integrated with manufacture of oxides of lead and lead antimony alloy.
18. All tourism projects between 200m—500 meters of High Water Line and at locations with an elevation of more than 1000 meters with investment of more than Rs. 5 crores.
19. Thermal Power plants.
20. Mining projects (with leases more than 5 hectares).
21. Highway Projects.
22. Tarred Roads in Himalayas and or Forest areas.
23. Distilleries.
24. Raw Skins and Hides.
25. Pulp, paper and newsprint.
26. Dyes.
27. Cement.
28. Foundries (Individual).
29. Electroplating.

## SCHEDULE—II

[See Sub-para I(a) of Para 3]

## APPLICATION FORM

1. (a) Name and Address of the project proposed :
- (b) Location of the projects:  
Name of the place:  
District, Tehsil:  
Latitude/Longitude:  
Nearest Airport/Railway Station :
- (c) Alternate sites examined and the reasons for selecting the proposed site :
- (d) Does the site conform to stipulated land use as per local land use plan:
2. Objectives of the project:
3. (a) Land Requirement:  
Agriculture Land :  
Forest land and Density of vegetation.  
Other (specify):
- (b) (i) Land use in the Catchment/within 10 Kms. radius of the proposed site
- (ii) Topography of the area indicating gradient, aspects and altitude ;
- (iii) Erodability classification of the proposed land ;
- (c) Pollution sources existing in 10 km. radius and their impact on quality of air, water & land:
- (d) Distance of the nearest National Park/Sanctuary/ Biosphere Reserve/Monuments/heritage site/Reserve Forest:
- (e) Rehabilitation on plan for quarries/borrow areas:
- (f) Green belt plan:
- (g) Compensatory afforestation plan:
4. Climate and Air Quality:  
(a) Windrose at site;
- (b) Max./Min./Mean annual temperature
- (c) Frequency of inversion:
- (d) Frequency of cyclones/tornadoes/cloud burst :
- (e) Ambient air quality data:
- (f) Nature & concentration of emission of SPM, Gas (Co, Co<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CH<sub>4</sub> etc.) from the project :
5. Water balance :  
(a) Water balance at site :
- (b) Lean season water availability:  
Water Requirement :
- (c) Source to be tapped with competing users (River, lake, Ground, Public supply):
- (d) Water quality :
- (e) Changes observed in quality and quantity of ground water in the last 15 years and present charging & extraction details:
- (f) (i) Quantum of waste water to be released with treatment details :
- (ii) Quantum of quality of water in the receiving body before and after disposal of solid wastes:
- (iii) Quantum of waste water to be released on land and type of land :

(g) (i) Details of reservoir water quality with necessary Catchment Treatment Plan ;

(ii) Command Area Development Plan ;

6. Solid wastes :

(a) Nature and quantity of solid wastes generated.

(b) Solid waste disposal method:

7. Noise and Vibrations:

(a) Sources of noise and Vibrations ;

(b) Ambient noise level:

(c) Noise and Vibration control measures proposed ;

(d) Subsidence problem if any with control measures:

8. Power requirement indicating source of supply : Complete environmental details to be furnished separately, if captive power unit proposed:

9. Peak labour force to be deployed giving details of:

— Endemic health problems in the area due to waste water/air/soil borne diseases:

— Health care system existing and proposal :

10. (a) Number of village and population to be displaced :

(b) Rehabilitation Master Plan :

11. Risk assessment report and Disaster Management Plan:

12. (a) Environmental Impact Assessment } Report  
(b) Environment Management Plan: } prepared as per  
(c) Detailed Feasibility Report : } guidelines of  
(d) Duly filled in questionnaire } time to time

13. Details of Environmental Management Cell:

I hereby give an undertaking that the data and information given above are true to the best of my knowledge and belief and I am aware that if any part of the data/information submitted is found to be false or misleading at any stage, the

project be rejected and the clearance given, if any, to the project is likely to be revoked at our risk and cost.

Signature of the applicant  
with name and full address.

Date .  
Place:

Given under the seal of  
Organisation on behalf of  
whom the applicant is  
signing.

In respect to item for which data are not required or is not available as per the declaration of project proponent, the project would be considered on that basis.

### SCHEDULE III

[See sub-para III(a) of Para 3]

### COMPOSITION OF THE EXPERT COMMITTEES FOR ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

1. The evaluation and assessment of development projects at the Central or State level will be undertaken by Experts Committees consisting of experts in each discipline constituted as under:

- (i) Eco-System Management
- (ii) Air/Water Pollution Control
- (iii) Water Resource Management
- (iv) Flora/Fauna conservation and management
- (v) Land Use Planning
- (vi) Social Sciences/Rehabilitation
- (vii) Project Appraisal
- (viii) Ecology
- (ix) Environmental Health
- (x) Subject Area Specialists
- (xi) Representatives of NGOs/persons concerned with environmental issues.

2. The Chairman will be outstanding and experienced ecologist or environmentalist or technical professional or wide managerial experience in the relevant development sector.

3. The representative of Impacts Assessment Agency/Central/State will act as a Member-Secretary.

4. Chairman and Members will serve in their individual capacities except those specifically nominated as representatives.

5. The Membership of a Committee shall not exceed 15.

